

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

प्रलिस के लयः

कॉर्पोरेट गवर्नेंस, केंद्रीय जाँच ब्यूरो, बैंकग वनियमन अधनियम

मेन्स के लयः

कॉर्पोरेट गवर्नेंस और संबधति मुददे

चर्चा में क्यों?

चंदा कोचर (ICICI बैंक की पूरव CEO) कॉर्पोरेट जगत में धोखाधड़ी संबधी खतरे के सचेतक के रूप में शामिल हैं ।

- **केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)** ने आरोप लगाया है कऱICICI बैंक ने **बैंकग वनियमन अधनियम**, RBI के दशऱनरदेशों और बैंक की क्रेडिट नीतऱका उल्लंघन करते हुए वेणुगोपाल धूत दवारा प्रवर्तति वीडयोकॉन समूह की कंपनयों को 3,250 करोड़ रुपए का क्रेडिट स्वीकृत कयऱ था ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

■ परचयः

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस नयऱमों, प्रथाओं और प्रक्रयऱओं की प्रणाली को संदरभति करता है, इसके दवारा एक कंपनी को नरदेशति और नयऱतरति कयऱ जाता है, जो यह सुनश्चिति करने में महत्त्वपूरण भूमकऱ नभऱता है कऱ वयवसाय नैतिकि रूप से तथा उनके हतिधारकों के सर्वोत्तम हति में चलाए जाते हैं ।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रमुख ज़मिमेदारयों में से एक कॉर्पोरेट लालच को रोकना तथा यह सुनश्चिति करना है कऱ वयवसायों को उत्तरदायी और पारदर्शी तरीके से संचालति कयऱ जाए ।
- मज़बूत नैतिकि मानकों को लागू करके तथा वयक्तयों को उनके कार्यों के लयऱ उत्तरदायी बनाकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लालच को रोकने और शेयरधारकों, ग्राहकों एवं वयऱपक समुदाय के हतऱों की रक़षा करने में मदद कर सकता है ।

■ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सदिधांतः

○ नषिपकषताः

- नदिशक मंडल को शेयरधारकों, करमचारयों, वकिरेताओं और समुदायों के साथ उचित एवं समान वचऱर से वयवहार करना चाहयऱ ।

○ पारदर्शतिः

- बोर्ड को वतऱतीय प्रदर्शन, हति संबधी मतभेद और शेयरधारकों एवं अन्य हतिधारकों को ज़ोखमि जैसी स्थतऱिके बारे में **मंसमय पर सटीक तथा स्पष्ट जानकारि प्रदान करनी चाहयऱ ।**

○ ज़ोखमि प्रबंधनः

- बोर्ड और प्रबंधन को सभी प्रकार के **ज़ोखमिों का नरिधारण तथा उन्हें नयऱतरति करना चाहयऱ ।** उन्हें प्रबंधति करने के लयऱ संबद्ध सफऱरशऱों पर कार्रवाई करनी चाहयऱ । उन्हें सभी संबधति पकषों को ज़ोखमिों की मौजूदगी तथा स्थतऱिके बारे में सूचिति करना चाहयऱ ।

○ ज़मिमेदारीः

- **बोर्ड कॉर्पोरेट मामलों और प्रबंधन गतवधियों की नगरऱनी के लयऱ ज़मिमेदार है ।**
- इसे कंपनी की प्रगतऱ और प्रदर्शन के बारे में पता होना चाहयऱ, साथ ही उसका समर्थन करना चाहयऱ । इसकी ज़मिमेदारी में CEO की भरती और नयुक्तऱ करना भी शामिल है । इसे कऱसी कंपनी एवं उसके नवऱशकों के सर्वोत्तम हति में कार्य करना चाहयऱ ।

○ जवाबदेहीः

- बोर्ड को **कंपनी की गतवधियों के उद्देश्य और उसके आचरण के परणऱमों की वयऱख्या करनी चाहयऱ ।** बोर्ड एवं कंपनी का नेतृत्व कंपनी की कषमता एवं प्रदर्शन के आकलन के लयऱ जवाबदेह है । इसे शेयरधारकों के महत्त्व के मुददों को संप्रेषति करना चाहयऱ ।

भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के संदर्भ में नैतिक मुद्दे:

- **व्यक्तिगत रुचि के बीच मतभेद:**
 - शेयरधारकों की कीमत पर संभावित रूप से व्यक्तिगत रुचि को समृद्ध करने वाले प्रबंधकों की चुनौती एक बड़ी समस्या है **हाल ही की एक घटना में** ICICI बैंक की पूर्व कार्यकारी चंदा कोचर ने अपने पता के लिये एक व्यापार के हिस्से के रूप में वीडियोकॉन कंपनी को ऋण स्वीकृत किया।
- **कमज़ोर बोर्ड:**
 - अनुभव और पृष्ठभूमि की विविधता का अभाव इन बोर्डों की कमज़ोरी का एक प्रमुख वषिय रहा है। शेयरधारकों के व्यापक हितों के मामले में बोर्ड के प्रदर्शन पर सवाल उठते रहे हैं।
- **स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण:**
 - परिवार द्वारा संचालित कंपनियों के मामले में भारत की कुछ शीर्ष कंपनियों सहित अधिकांश कंपनियों में स्वामित्व और प्रबंधन को अलग करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- **स्वतंत्र नदिशक:**
 - स्वतंत्र नदिशक पक्षपातपूर्ण होते हैं और प्रमोटर्स की अनैतिक प्रथाओं की जाँच करने में सक्षम नहीं होते हैं।

संबंधित पहलें

- भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल की ज़िम्मेदारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) एवं **भारतीय प्रतभिति और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI)** पर है। उदारीकरण के बाद वर्ष 1990 के दशक में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र को बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है।
- सेबी खंड 49 के माध्यम से भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नगिरानी और नयिमन करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013** बड़े हुए और नए अनुपालन मानदंडों के माध्यम से प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग एवं पारदर्शिता को बढ़ाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिये औपचारिक संरचना प्रदान करता है।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार:

- **विविध बोर्ड बेहतर बोर्ड:**
 - इस संदर्भ में व्यापक 'विविधता' है, जिसमें लिंग, जातीयता, कौशल और अनुभव शामिल हैं।
- **मज़बूत जोखमि प्रबंधन नीतियाँ:**
 - बेहतर नरिणय लेने के लिये प्रभावी और मज़बूत जोखमि प्रबंधन नीतियों को अपनाना क्योंकि यह सभी नगिमों के सामने आने वाले **रसिक-रविर्ड ट्रेड-ऑफ** के मामले में गहरी अंतरदृष्टि विकसित करता है।
- **प्रभावी शासन अवसंरचना:**
 - चूँकि अंततः बोर्ड किसी संगठन के सभी कार्यों और नरिणयों के लिये ज़िम्मेदार होता है, इसलिये संगठनात्मक व्यवहार को नरिदेशित करने के लिये वशिषिट नीतियों की आवश्यकता होगी।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये **बोर्ड और प्रबंधन के बीच उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से नरिधारित किया गया है**, बोर्ड के लिये प्रतनिधिमिडलों के संबंध में नीतियाँ विकसित करना वशिष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन:**
 - बोर्डों को मूल्यांकन में सामने आई कमज़ोरियों को दूर करके अपनी शासन प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिये।
- **संवाद:**
 - बोर्ड के साथ शेयरधारकों के संवाद को सुगम बनाना महत्त्वपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके साथ शेयरधारक किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. सत्यम कांड (2009) के परपिक्ष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये कॉर्पोरेट प्रशासन में लाए गए परविरतनों पर चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. 'शासन', 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' शब्दों से आप क्या समझते हैं?(2016)

स्रोत: लाइव मटि

